Endorsement on FW7-13800/2018(1), dated 26-6-2018 of the High Court of Kerala, Kochi - 31

Copy of Government of India letter No. 15011/80/2018, dt., 25.5.2017 is communicated to the undermentioned Sections for information and necessary action.

(By order)

D.Narayanan Moothath
Finance Officer(i/c)

All Sections of the High Court,

The IT Section, High Court (for displaying the above information in the website of the High Court of Kerala),

The File.

No. 15011/80/2018-Jus(AU)
Government of India
Ministry of Law & Justice
(Department of Justice)

RL(F)

Jaisalmer House, 26, Mansingh Road
New Delhi, 25th May, 2017

To

The Registrar General,
High Court of ....

The Secretary (Law)
Government of State of .....

Member Secretary, NALSA

Director-in-charge, NJA, Bhopal

Sub: Publicizing of MDR Waiver and revised BHIM Incentive – reg.

Sir,

I am directed to forward a copy each of following documents on the subject for your information and necessary action, please :-

(i) The Gazette of India dated 26.4.2018 issued by Ministry of Electronics and Information Technology regarding continuation and modification of BHIM Cash back Scheme for Merchants.

(ii) DO letter No. 12(23)/2017-DPD dated 26.4.2018 of Shri Gopalakrishnan S, IAS, Joint Secretary, Ministry of Electronics and Information Technology alongwith Gazette of India dated 27.12.2017 issued by Ministry of Electronics and Information Technology regarding subsidizing MDR charges on Debit Cards/BHIM UPI/AePS transactions of value less than or equal to Rs 2,000.00.

Please acknowledge.

Yours faithfully,

Encl : as above

(Prem Lata Kaushik)
Under Secretary to the Govt. of India
Tel No. 23072549

Copy to :-

All Sections of DoJ.

260

List of Registrar General, All High Courts

1. The Registrar (Judicial), Supreme Court of India New Delhi	14 The Registrar General, Kerala High Court Ernakulam-682031.
2. The Registrar General, Allahabad High Court, Allahabad-211001	15 The Registrar General, Madhya Pradesh High Court, Jabalpur-482002.
3. The Registrar General, Andhra Pradesh High Court, Hydrabad-500266.	16 The Registrar General, Madras High Court, Chennai-600001.
4. The Registrar General, Bombay High Court, Mumbai-400032.	17 The Registrar General, Meghalaya High Court, Shillong
5. The Registrar General, Calcutta High Court Kolkata-600001.	18 The Registrar General, Manipur High Court, Imphal
6. The Registrar General, Chhattisgarh High Court, Bilaspur-495001	19 The Registrar General, Orissa High Court, Cuttack-753002.
7 The Registrar General, Delhi High Court New Delhi-110001	20 The Registrar General, Patna High Court, Patna-800001.
8 The Registrar General, Gauhati High Court, Guwahati-781001.	21 The Registrar General, Punjab & Haryana High Court Chandigargh-161001
9 The Registrar General, Gujarat High Court Ahmedabad-380060.	22 The Registrar General, Rajasthan High Court Jodhpur-342001.
10 The Registrar General, Himachal Pradesh High Court, Shimla-171001	23 The Registrar General, Sikkim High Court Gangtok-737101.
11. The Registrar General, Jammu & Kashmir High Court, Jammu-180001/Srinagar-190001.	24 The Registrar General, Uttarakhand High Court, Nanital-263001.
12 The Registrar General, Jharkhand High Court, Ranchi-834002	25 The Registrar General, Tripura High Court, Agartala
13 The Registrar General, Karnataka High Court Bangalore-560001.	

NAME OF THE STATES

- LAW SECRETARY :-

ANDHRA PRADESH	ARUNACHAL PRADESH
ASSAM	BIHAR
CHHATTISGARH	DELHI
GOA	GUJARAT
HARYANA	HIMACHAL PRADESH
JAMMU & KASHMIR	JHARKHAND
KARNATAKA	KERALA
MADHYA PRADESH	MAHARASHTRA
MANIPUR	MEGHALAYA
MIZORAM	NAGALAND
ORISSA	PUNJAB
PUDUCHERRY	RAJASTHAN
SIKKIM	TAMIL NADU
TRIPURA	UTTAR PRADESH
UTTARAKHAND	WEST BENGAL
CHANDIGARH	DAMAN & DIU
LAKSHADWEEP	
ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS	
DADRA & NAGAR HAVELI	

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 174] नई दिल्ली, शनिवार, मई 12, 2018/वैशाख 22, 1940

No. 174] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 12, 2018/VAISAKHA 22, 1940

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2018

विषय: व्यापारियों के लिए भीम (भारत इंटरफेस फॉर मनी) कैशबैक योजना का विस्तार और संशोधन।

सं. 12/13/2017-**डीपीडी-एमईआईटीवाई**.— जबकि, केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 5 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 12(84)/2017-डीपीडी के जरिए भीम आधार व्यापारियों के अंगीकरणों को प्रोत्साहन देकर तथा भीम-यूपीआई प्लेटफार्मों के जरिए लेनदेनों को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापारियों के बीच भीम-यूपीआई के प्रयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से व्यापारियों के लिए "भीम (भारत इंटरफेस फॉर मनी) कैशबैक" नामक एक योजना अधिसूचित की है।

जबकि, केंद्र सरकार ने भारत सरकार, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की दिनांक 14 अगस्त, 2017 की अधिसूचना सं. 12/13/2017 –डीपीडी के जरिए योजना के प्रचालन को 31 मार्च, 2018 तक विस्तारित किया है।

और जबकि, केंद्र सरकार ने योजना की समीक्षा की है।

अब केंद्र सरकार एतदद्वारा व्यापारियों के लिए भीम (भारत इंटरफेस फॉर मनी) कैशबैक योजना नामक विषय के अंतर्गत अधिसूचित भारत सरकार, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की 5 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 12(84)/2017-डीपीडी में निम्नलिखित संशोधन करती है:-

"विषय: <u>व्यापारियों के लिए भीम (भारत इंटरफेस फॉर मनी) प्रोत्साहन योजना</u>"

1. पैराग्राफ 2 और 3 में किए गए प्रावधानों के लिए उपर्युक्त पैराग्राफों को निम्नलिखित प्रावधानों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है अर्थात:-

<u>व्यापारियों के लिए भीम प्रोत्साहन योजना</u>

1.1 पैराग्राफ 2.1: इस योजना का क्षेत्र उन फी एप्प प्रयोक्ताओं तक सीमित होगा जिन्होंने स्वयं को "मै व्यापारी हूं" के तौर पर घोषित किया है तथा जिनके पास एमसीसी "000" है तथा जो व्यापारी किसी ऐसे बैंक द्वारा ऑनबोर्ड किए गए हैं जो भीम-यूपीआई के जरिए भुगतान स्वीकार करते हैं या उनके पास "000" से भिन्न एमसीसी है। इस योजना की अवधि 12 महीने तक है यानि 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक तथा इसे सरकार के निदेशों के आधार पर कभी भी पुनरीक्षित किया जा सकता है।

1.2 पैराग्राफ 2.3: व्यापारियों के लिए प्रोत्साहन स्लैब है :-

क. **भीम मर्चेंट** : ऐसा भीम एप्प प्रयोक्ता जिसने स्वयं को "मै व्यापारी हूं" के तौर पर घोषित किया है तथा जिनके पास एमसीसी "000" है निम्नलिखित प्रोत्साहन के लिए पात्र होगा :

क्रेडिट लेनदेनों की संख्या (प्रतिमाह)	**दुकानदारों को प्रोत्साहन (माह के अंत में)**	**शर्तें**
प्रोत्साहन प्राप्त करना प्रारंभ करने के लिए किया जाने वाला न्यूनतम लेनदेन =>10	50 रु. प्रति लेनदेन की प्रोत्साहन की ऊपरी सीमा के साथ लेनदेन मूल्य का 10%	कैशबैक के लिए योग्य न्यूनतम लेनदेन मूल्य 25 रु. है। प्रति माह प्रति व्यापारी अधिकतम कैशबैक 1000 रुपए है। "माह" की गणना के लिए कलेण्डर माह का प्रयोग किया जाएगा।

ख) भीम – यूपीआई व्यापारी : यूपीआई के जरिए भुगतान प्राप्त करने वाला और "0000" से भिन्न एमसीसी वाला किसी भी बैंक का व्यापारी

क्रेडिट लेनदेनों की संख्या (प्रतिमाह)	**दुकानदारों को प्रोत्साहन (माह के अंत में)**	**शर्तें**
प्रोत्साहन प्राप्त करना प्रारंभ करने के लिए किया जाने वाला न्यूनतम लेनदेन =>5	50 रु. के प्रति लेनदेन पर प्रोत्साहन की ऊपरी सीमा के साथ लेनदेन मूल्य का 10%	प्रोत्साहन के लिए योग्य न्यूनतम लेनदेन मूल्य 25 रु. है। प्रति माह प्रति व्यापारी अधिकतम प्रोत्साहन 1000 रुपए है। "माह" की गणना के लिए कलेण्डर माह का प्रयोग किया जाएगा।

1.3 पैराग्राफ 3.1 प्रोत्साहन के लिए अर्हता हेतु दुकानदारों के परिभाषित लेनदेन मानदंड निम्नानुसार हैं :

क. स्वयं को "मैं दुकानदार हूं" घोषित करने वाले और एमसीसी "0000" वाले भीम एप्प प्रयोक्ता के लिए प्रतिमाह न्यूनतम 10 क्रेडिट लेनदेन और यूपीआई के जरिए भुगतान प्राप्त करने वाले तथा "0000" से अन्य एमसीसी वाले किसी भी बैंक के दुकानदार के लिए प्रतिमाह न्यूनतम 5 क्रेडिट लेनदेन।

ख. प्रोत्साहन के लिए योग्य लेनदेनों के लिए न्यूनतम लेनदेन मूल्य 25 रु. है।

1.4 पैराग्राफ 3.2 : अन्य मानदण्ड :

i. व्यापारी भीम एप्प प्रयोक्ता हो सकता है या उसे किसी वैध भीम-यूपीआई ग्राहक से भीम-यूपीआई से भुगतान प्राप्त कर सकता है।

ii. व्यापारियों के लिए भीम प्रोत्साहन योजना एक मासिक योजना है तथा इस योजना के अंतर्गत "माह" की गणना के लिए कलेण्डर माह का प्रयोग किया जाएगा।

iii. बाद में कलेण्डर माह के 10वें दिन या इससे पहले योग्य ग्राहकों के संबंधित खातों में प्रोत्साहन क्रेडिट किए जाएंगे।

iv. व्यापारियों को व्यापारियों के लिए भीम प्रोत्साहन योजना के साथ-साथ व्यक्तियों के लिए कैशबैक योजना के अंतर्गत भी प्रोत्साहन प्राप्त हो सकते हैं। (व्यापारी और व्यक्ति का ओवरलेप स्वीकार्य है)

अनुबंध 1- हटाया जाना है।

अनुबंध 2- हटाया जाना है।

गोपालकृष्णन एस., संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th April, 2018

Subject: Continuation and modification of BHIM Cashback Scheme for Merchants

No. 12/13/2017–DPD-MeitY..—WHEREAS, the Central Government vide notification of Government of India, Ministry of Electronics and Information Technology No. 12(84)/2017-DPD dated 05th June 2017, has notified a Scheme namely 'BHIM (Bharat Interface for Money) Cashback Scheme for Merchants', with the objective to promote usage of BHIM-UPI amongst merchants by incentivizing its adoptions and also to encourage transactions via BHIM-UPI platform.

WHEREAS, the Central Government vide notification of Government of India, Ministry of Electronics and Information Technology No 12/13/2017-DPD dated 14th August 2017, modified and extended the operation of the scheme till 31st March 2018.

AND WHEREAS, the Central Government has reviewed the scheme.

Now, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of Government of India, Ministry of Electronics and Information Technology No. 12(84)/2017-DPD dated 5th June 2017, notified under the subject namely 'BHIM (Bharat Interface for Money) Cashback Scheme for Merchants':-

Subject: "BHIM (Bharat Interface for Money) incentive scheme for Merchants"

1. For provisions in paragraph 2 & 3, the following provisions in the said paragraphs are substituted namely:-

BHIM incentive scheme for Merchants

1.1 Paragraph 2.1: The scope of the scheme shall be limited to BHIM App users who have declared themselves as "I am a merchant" and have MCC "0000" and Merchants on-boarded by any bank receiving payment through BHIM-UPI and have MCC other than "0000". The duration of the scheme is 12 months i.e. 1st April 2018 to 31st March 2019 and can be reviewed anytime based on the Government directions.

1.2 Paragraph 2.3: The incentive slabs for merchants are:

a) **BHIM Merchant :** BHIM App User who has declared himself as "I am a merchant" and have MCC "0000" will be eligible for following incentive:

No. of credit transactions (per month)	***Incentive to the merchant (at the end of the month)***	***Conditions***
Minimum credit transactions to be done to start earning the incentive =>10	10% of the transaction value with an upper cap of incentive of Rs 50 per transaction	Minimum transaction value eligible for incentive is Rs. 25; Maximum incentive is Rs. 1000 per merchant per month. Calendar month will be used for calculation of "month"

a) **BHIM-UPI merchants :** Merchant of any bank receiving payment through UPI and have MCC other than "0000"

No. of credit transactions (per month)	***Incentive to the merchant (at the end of the month)***	***Conditions***
Minimum transactions to be done to start earning the incentive =>5	10% of the transaction value with an upper cap of incentive of Rs 50 per transaction	Minimum transaction value eligible for incentive is Rs. 25; Maximum incentive is Rs. 1000 per merchant per month. Calendar month will be used for

		calculation of "month"

1.3 Paragraph 3:

3.1: Defined transactions criteria for merchants to qualify for the incentive are:

a) Minimum of 10 credit transactions per month for BHIM App User who has declared himself as "I am a merchant" and have MCC "0000" and minimum of 5 credit transactions per month for the merchant of any bank receiving payment through UPI and have MCC other than " 0000".

b) The minimum transaction value for the transactions eligible for incentive is Rs 25.

1.4 Paragraph 3.2: Other criteria:

i) Merchant could be a BHIM app user or receiving payment through BHIM-UPI from any valid BHIM-UPI customer.

ii) BHIM incentive scheme for merchant is a monthly scheme and calendar month will be used for calculation of "month" under the scheme.

iii) Incentive will be credited to linked accounts of the eligible customers on or before 10th day of the subsequent calendar month.

iv) Merchant can earn incentive under BHIM incentive scheme for merchants as well as BHIM cashback scheme for Individuals. (The overlap of merchant and individual is acceptable).

Annexure 1- To be deleted

Annexure 2 – Tobe deleted

GOPALAKRISHNAN S., Joint Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2018

विषय: व्यक्तियों के लिए भीम (भारत इंटरफेस फॉर मनी) रेफरल बोनस योजना का विस्तार और संशोधन (अब व्यक्तियों के लिए भीम कैशबैक योजना के नाम से पुर्ननामित)।

सं.12/13/2017-डीपीडी- एमईआईटीवाई.—जबकि, केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 5 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 12(84)/2017-डीपीडी के जरिए भीम प्लेटफॉर्म पर नए प्रयोक्ताओं को लाने के लिए भीम के मौजूदा प्रयोक्ताओं को प्रोत्साहन देने और भीम के प्रयोक्ताओं की संख्या बढ़ाने के लक्ष्य के साथ भीम का प्रयोग करते हुए लेनदेन करने के लिए नवीन प्रयोक्ताओं को प्रोत्साहित करने और इसके माध्यम से लेनदेनों को बढ़ाने के उद्देश्य से 'भीम (भारत इंटरफेस फॉर मनी) कैशबैक' नामक एक योजना अधिसूचित की है।

जबकि, केंद्र सरकार ने दिनांक 14 अगस्त, 2017 की अधिसूचना सं. 12/13/2017 –डीपीडी के जरिए योजना को संशोधित किया और इसके प्रचालन को 31 मार्च, 2018 तक विस्तारित किया।

और जबकि, केंद्र सरकार ने योजना की समीक्षा की है।

अब केंद्र सरकार, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 5 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 12(84)/2017-डीपीडी, व्यक्तियों के लिए भीम (भारत इंटरफेस फॉर मनी) रेफरल योजना के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है, जो अब व्यक्तियों के लिए भीम कैशबैक योजना के रूप में नामित की गई है, में एतदद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है:-

पैराग्राफ 1, 2 और 3 में किए गए प्रावधानों के लिए उपर्युक्त पैराग्राफों में निम्नलिखित प्रावधानों को उपयुक्त ढंग से प्रतिस्थापित किया जाता है अर्थात :-

1.1 पैराग्राफ 1.4 : डिजिटल भुगतानों को प्रोत्साहित करने के लिए बाजार में शुरू की गई नवीन प्रौद्योगिकियों, प्लेटफॉर्मों और एप्स का अंगीकरण करने के लिए प्रोत्साहन योजनाओं का व्यापक रूप से प्रयोग हुआ है तथा ये प्रभावशाली साबित हुई हैं। "व्यक्तियों के लिए

भीम कैशबैक योजना" को भीम एप्प पर नवीन प्रयोक्ताओं की ऑनबोर्डिंग को प्रोत्साहित करने तथा भीम-यूपीआई आधारित लेनदेन के प्रयोग को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस योजना के उद्देश्य निम्नानुसार हैं :

भीम एप्प के डाउनलोड, इंस्टॉलिंग, भीम एप्प को अपने बैंक खातों के साथ लिंक करने वाले प्रयोक्ताओं की संख्या बढ़ाना और पहला वित्तीय लेनदेन सफलतापूर्वक करना।

भीम-यूपीआई के प्रयोग द्वारा लेनदेन की संख्या में बढ़ोत्तरी करना।

व्यक्तियों के लिए भीम कैशबैक योजना

1.2 पैराग्राफ : 2.1 - इस योजना में दो घटक हैं क) भीम एप्प पर ऑनबोर्डिंग के लिए प्रोत्साहन और ख) भीम-यूपीआई पर लेनदेन के लिए प्रोत्साहन। घटक 'क' के कार्यक्षेत्र में केवल भीम एप्प प्रयोक्ता ही आते हैं और घटक 'ख' के कार्यक्षेत्र में भीम एप्प के प्रयोक्ताओं के साथ-साथ बैंकों के भीम-यूपीआई एप्प भी आते हैं। इस योजना की अवधि 12 महीने यानि 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक है तथा इसे सरकार के निदेशों के आधार पर कभी भी पुनरीक्षित किया जा सकता है।

1.3 पैराग्राफ 2.3 – "ऑनबोर्डिंग के लिए प्रोत्साहन" का भुगतान भीम एप्प के ऐसे नवीन प्रयोक्ताओं को किया जाएगा जो अपने भीम एप्प को सफलतापूर्वक डाउनलोड कर उसे अपने बैंक के खाते/खातों के साथ जोड़ेंगे तथा भीम एप्प के जरिए सफलतापूर्वक एक वित्तीय लेनदेन करेंगे। "लेनदेन पर प्रोत्साहनों" का भुगतान ऐसे प्रयोक्ताओं को किया जाएगा जो भीम एप्प और/या बैंकों के भीम-यूपीआई एप्प पर वित्तीय लेनदेन करते हैं।

1.4 पैराग्राफ : 2.4 – प्रोत्साहन निम्नलिखित के अनुसार दिए जाएंगे :

तालिक-I

भीम एप्प पर ऑनबोर्डिंग के लिए प्रोत्साहन

क्र.सं.	ऑनबोर्डिंग हेतु प्रोत्साहन	**प्रति भीम एप्प प्रयोक्ता कुल राशि (रु.में)**
1.	नये भीम एप्प को प्रयोक्ता द्वारा डाउनलोड, इंस्टॉल किए जाने और सफलतापूर्वक एक वित्तीय लेनदेन पूर्ण किए जाने पर	51

तालिक-II

भीम एप्प पर लेनदेनों हेतु प्रोत्साहन

क्र.सं.	लेनदेनों पर प्रोत्साहन	राशि (रु. में)		शर्तें
1.	विशिष्ट वित्तीय लेनदेन के लिए भीम और बैकों भीम-यूपीआई एप्प प्रयोक्ता	25 प्रति लेनदेन		न्यूनतम लेनदेन मूल्य 100 रु. होना चाहिए। प्रति कलेंडर माह अधिकतम 20 विशिष्ट लेनदेनों के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। केवल विशिष्ट लेनदेन ही प्रोत्साहन केलिए पात्र होंगे।
2.	भीम और वित्तीय लेनदेन के लिए बैंको के भीम-यूपीआई एप्प प्रयोक्ता	**प्रति माह लेनदेनों की संख्या**	**प्रति माह प्रोत्साहन (रु.)**	न्यूनतम लेनदन मूल्य 10 रु. होना चाहिए। "माह" की गणना के लिए कलेंडर माह का प्रयोग किया जाएगा।
		>= 25 पर 50 से कम	100	
		>= 50 पर 100 से कम	200	
		> 100	250	

1.5 पैराग्राफ 3.1: प्रोत्साहन अर्जित करने के लिए योग्यता:

क) "भीम एप्प पर ऑनबोर्डिंग हेतु प्रोत्साहन" के लिए प्रयोक्ता को भीम एप्प को डाउनलोड, इंस्टॉल बैंक खाते/खातों के साथ जोड़ना होता है तथा किसी भी मूल्य का वित्तीय लेनदेन सफलतापूर्वक पूरा करना होता है। प्रोत्साहन का भुगतान केवल एक बार किया जाएगा तथा यह केवल नवीन प्रयोक्ताओं के लिए ही किया जाएगा।

ख) तालिका-II में उल्लिखित शर्तों के अनुसार "भीम-यूपीआई पर लेनदेनों हेतु प्रोत्साहन" का भुगतान विशिष्ट भुगतानों सहित कुल वित्तीय लेनदेनों दोनों के लिए अलग-अलग किया जाएगा।

I. विशिष्ट लेनदेनों पर प्रोत्साहन के लिए भीम एप्प और/या बैंकों के भीम-यूपीआई एप्प पर वित्तीय लेनदेन करने वाले प्रयोक्ता प्रत्येक कलेंडर माह में अधिकतम 20 विशिष्ट लेनदेनों पर प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। न्यूनतम लेनदेन मुल्य 100 रु. होना चाहिए।

II. 10रु. या इससे अधिक मूल्य के प्रयोक्ता लेनदेन तालिका-II की क्र.सं. 2 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार प्रोत्साहन के लिए पात्र होंगे।

ग) हटाया जाना है।

1.6 पैराग्राफ 3.2 : हटाया जाना है।

1.7 पैराग्राफ 3.3 :

क. भीम एप्प और बैंकों या *99# के भीम-यूपीआई एप्प से केवल वैध अनुमोदित लेनदेनों पर योजना हेतु विचार किया जाएगा।

ख. किसी भी दो भीम-यूपीआई प्रयोक्ताओं/वीपीए के बीच "विशिष्ट लेनदेन" प्रथम वित्तीय लेनदेन है।

ग. लेनदेनों पर प्रोत्साहन का भुगतान उस प्रयोक्ता को किया जाएगा जिसका खाता "वैध वित्तीय लेनदेन" के लिए डेबिट किया गया है।

घ. "वैध वित्तीय लेनदेन": 1 रु. या इससे अधिक तथा 100,000 रु. या इससे कम की राशि का एक बैंक खाते से अन्य बैंक खाते में अंतरण।

ङ. हटाया जाना है।

च. हटाया जाना है।

अनुबंध 1- हटाया जाना है।

अनुबंध 2- हटाया जाना है।

गोपालकृष्णन एस., संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th April, 2018

Subject: Continuation and modification of BHIM (Bharat Interface for Money) referral bonus scheme for individuals (Now named as BHIM Cashback scheme for Individuals)

No. 12/13/2017–DPD-MeitY.—WHEREAS, the Central Government vide notification of Government of India, Ministry of Electronics and Information Technology No. 12(84)/2017-DPD dated 05th June 2017, has notified a Scheme namely 'BHIM (Bharat Interface for Money) Referral Scheme for Individuals', with the objective to incentivize the existing users of BHIM to bring new users on BHIM platform and encourage new users to do transactions using BHIM with the target to increase the number of users for BHIM and also increase the transaction thereof.

WHEREAS, the Central Government vide notification of Government of India, Ministry of Electronics and Information Technology No 12/13/2017-DPD dated 14th August 2017, modified and extended the operation of the scheme till 31st March 2018.

AND WHEREAS, the Central Government has reviewed the scheme.

Now, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of Government of India, Ministry of Electronics and Information Technology No. 12(84)/2017-DPD dated 5th June 2017, notified under the subject namely 'BHIM (Bharat Interface for Money) Referral Scheme for Individuals' now named as BHIM cashback scheme for Individuals:-

For provisions in paragraph 1, 2 & 3, the following provisions in the said paragraphs are substituted namely:-

1.1 Paragraph 1.4: In the promotion of digital payments, incentive schemes are widely used to promote adoption of the new technologies, platforms and apps that are launched in the market and it has proved effective. The **"BHIM cashback scheme for individuals"** has been designed to encourage the onboarding of new users on the BHIM App and increase the usage of BHIM-UPI based transactions. The objectives of the scheme are:

- Increase the number of users downloading, installing, linking BHIM App with their bank accounts and making first successful financial transaction.
- Increase in the number of transactions using BHIM-UPI

BHIM cashback scheme for Individuals

1.2 Paragraph: 2.1 The scheme has two components a) Incentive for onboarding over BHIM App and b) Incentive on transactions over BHIM-UPI. The scope of the component 'a' is only BHIM app users and the scope of the component 'b' is the users of BHIM app as well as BHIM-UPI apps of the banks. The duration of the scheme is 12 months i.e. 1st April 2018 to 31st March 2019 and can be reviewed anytime based on the Government directions.

1.3 Paragraph: 2.3 The "incentive for onboarding" will be paid to the new users of the BHIM app who successfully download the BHIM app, link the BHIM app with their bank account/s and undertake one successful financial transaction through BHIM app. The "incentive on transactions" will be paid to the users undertaking financial transactions on the BHIM app and/or BHIM-UPI apps of the banks.

1.4 Paragraph: 2.4 The incentives will be paid as per the following:

TABLE-I

Incentive for onboarding on BHIM app

S. No.	Incentive for onboarding	Total amount (in Rs.) per BHIM app user
1	New BHIM app user on downloading , installing and successfully completing one financial transaction	51

TABLE-II

Incentive on transactions over BHIM-UPI

S. No.	Incentive on transactions	Amount (in Rs.)		Conditions
1	BHIM and BHIM-UPI app users of banks for unique financial transaction.	25 per transaction		Minimum transaction value should be Rs 100. The incentive will be paid for maximum 20 unique transactions per calender month. Only unique transactions will be eligible for incentive.
2	BHIM and BHIM-UPI app users of banks for financial transaction.	**Number of transactions per month**	**Incentive per month (Rs.)**	Minimum transaction value should be Rs 10. Calendar month will be used for calculation of "month"
		>=25 but less than 50	100	
		>=50 but less than 100	200	
		>=100	250	

1.5 Paragraph 3.1: Qualification to earn incentives:

a) For "incentive for onboarding on BHIM app", the user has to download, install and link BHIM app with the bank account/s and successfully complete one financial transaction of any value. The incentive will paid

only one time and for the new users only.

b) "Incentive for transactions over BHIM-UPI" will be paid separately for both unique transactions as well as total financial transactions as per the conditions mentioned in para Table-II.

I. For incentive on unique transactions the users undertaking financial transactions on the BHIM app and/or BHIM-UPI apps of the banks shall be entitled to receive incentive on maximum 20 unique transactions in each calendar month. Minimum transaction value should be Rs 100.

II. All user transactions of value equal to or above Rs 10 will be eligible for incentive as per the conditions mentioned in S.No. 2 of Table-II.

c) To be deleted

1.6 Paragraph 3.2: To be deleted

1.7 Paragraph 3.3:

a. Only valid approved transactions from BHIM app and BHIM-UPI apps of banks or *99# will be considered for the scheme.

b. The "unique transaction" is the first financial transaction between any two BHIM-UPI users/VPA.

c. Incentive on the transactions will be paid to the user whose account is debited for the "valid financial transaction".

d. "Valid financial transaction": Money transfer from one bank account to another bank account of amount greater than or equal to Rs. 1 and less than on equal to Rs. 1,00,000.

e. To be deleted.

f. To be deleted.

Annexure 1: To be deleted
Annexure 2: To be deleted

GOPALAKRISHNAN S., Joint Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2018

विषय: भीम (भारत इंटरफेस फॉर मनी) आधार व्यापारी प्रोत्साहन योजना का विस्तार और संशोधन।

सं.12/9/2017- डीपीडी-एमईआईटीवाई.—जबकि, केंद्र सरकार ने भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-I, खण्ड-I में प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 23 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 12(84)/2017-डीपीडी के जरिए भीम आधार व्यापारियों के अंगीकरण को प्रोत्साहन देने तथा भीम आधार का प्रयोग करते हुए और गैर-संगठित क्षेत्र के साथ-साथ नागरिकों के बीच डिजिटल भुगतानों को प्रोत्साहित करने के लक्ष्य के साथ भीम (भारत इंटरफेस फॉर मनी) आधार व्यापारी प्रोत्साहन नामक एक योजना अधिसूचित की है।

जबकि, केंद्र सरकार ने भारत सरकार, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की दिनांक 14 अगस्त, 2017 की अधिसूचना सं. 12/13/2017–डीपीडी के जरिए योजना को संशोधित किया और इसके प्रचालन को 31 मार्च, 2018 तक विस्तारित किया।

और जबकि, केंद्र सरकार ने योजना की समीक्षा की है ।

अब, केंद्र सरकार एतदद्वारा व्यक्तियों के लिए 'भीम (भारत इंटरफेस फॉर मनी) आधार व्यापारी प्रोत्साहन', योजना नामक विषय के अंतर्गत अधिसूचित भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-I खण्ड- I में प्रकाशित भारत सरकार, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की 23 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 12(84)/2017-डीपीडी में निम्नलिखित संशोधन करती है:-

पैराग्राफ 2 और 3 में किए गए प्रावधानों के लिए उपर्युक्त पैराग्राफों को निम्नलिखित प्रावधानों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है अर्थात :-

-41-

1.1 पैराग्राफ 2.1 भीम आधार व्यापारी प्रोत्साहन योजना 31 मार्च, 2019 तक प्रचालन में रहेगी।

1.2 पैराग्राफ : 2.3 –

- आधार प्रमाणन के बारे में उपकरण को कोई भान (जानकारी) नहीं होगी, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन से उपकरण यानि माइक्रो-एटीएम/पीओएस, एमपीओएस, कियोस्क/टेबलेट/मोबाइल हैंडसेट इत्यादि को शामिल किया गया है, परन्तु व्यापारिक प्रतिष्ठान द्वारा माल और सेवाओं की बिक्री के लिए लेनदेन हो और भुगतान आधार संख्या और बॉयोमीट्रिक प्रमाणन द्वारा किया जाए। तथापि, माइक्रो एटीएम के जिरए व्यापारिक पत्र व्यवहार (बीसी) के जरिए नियमित रूप से किए जाने वाले बैंकिंग संबंधी लेनदेन को इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा।
- भीम आधार लेनदेनों के लिए प्रति लेनदेन 2 रुपए की न्यूनतम प्रोत्साहन और 50 रुपये की अधिकतम प्रोत्साहन के साथ 25 रुपए से अधिक या इसके समतुल्य और 10,000 रुपए से कम अथवा इसके समतुल्य राशि के लेनदेन मूल्य पर 5% की दर से प्रोत्साहन दिया जाए।
- लेनदेन मूल्य के 0.5% का संपूर्ण प्रोत्साहन अधिग्रहणकर्ता बैंक द्वारा व्यापारी को दिया जाना है तथा किसी भी अधिग्रहणकर्ता बैंक द्वारा अपनी बैंकिंग/प्रचालन संबंधी लागत को चुकाने के लिए प्रोत्साहन का कोई भी अंश नहीं रखा जा सकता है।

1.3 पैराग्राफ : 3.1 –

ख) प्रोत्साहन कार्यक्रम के अंतर्गत पात्र न्यूनतम और अधिकतम लेनदेन मूल्य क्रमश: 25 रु. और 10,000 रु. है।

1.4 पैराग्राफ : 3.2 –

(ii) भीम आधार प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य व्यापारी की प्रचालन संबंधी लागत को चुकाना तथा भीम आधार आधारित डिजिटल भुगतान संबंधी लेनदेन को प्रोत्साहित करना है।

2. अनुबंध 1-

क) "वैध वित्तीय लेनदेन - 25 रुपए से अधिक या इसके समतुल्य और 10,000 रुपए से कम अथवा इसके समतुल्य राशि का लेनदेन"।

3. अन्य शर्तें व निबंधन अपरिवर्तित रहेंगे।

गोपालकृष्णन एस., संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th April, 2018

Subject: Extension and modification in the BHIM (Bharat Interface for Money) Aadhaar Merchant Incentive Scheme

No. 12/9/2017–DPD-MeitY.—WHEREAS, the Central Government vide notification of Government of India, Ministry of Electronics and Information Technology No. 12(84)/2017-DPD dated 23rd June 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary Part-1 Section-1, notified a Scheme namely 'BHIM (Bharat Interface for Money) Aadhaar Merchant Incentive, with the aim to incentivize adoption of BHIM Aadhaar merchants and promote digital payments across un-organized sector as well as the citizens using BHIM Aadhaar.

WHEREAS, the Central Government vide notification of Government of India, Ministry of Electronics and Information Technology No 12/13/2017-DPD dated 14th August 2017, extended the operation of the scheme till 31st March 2018.

AND WHEREAS, the Central Government has reviewed the scheme.

Now, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of Government of India, Ministry of Electronics and Information Technology No. 12(84)/2017-DPD dated 23rd June 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary Part-1 Section-1, notified under the subject namely 'BHIM (Bharat Interface for Money) Aadhaar Merchant Incentive scheme:-

1. For provisions in paragraph 2 & 3, the following provisions in the said paragraphs are subsituted namely:-

1.1 Paragraph 2.1- The BHIM Aadhaar Merchant Incentive Scheme will be operational till 31st March 2019.

1.2 Paragraph 2.3 –

- Aadhaar Authentication be device agnostic and any device viz., Micro-ATM/PoS, mPoS, Kiosk/Tablet/Mobile Handset etc be covered provided that the transaction is for sale of goods & services by a merchant establishment and payment is by Aadhaar Number & Biometric authentication. However, regular Business Corresspondent (BC) banking transactions through microATM will not be covered under the scheme.
- BHIM Aadhaar transactions may be given an incentive @ 0.5% of the transaction value for the transactions greater than or equal to Rs 25 and less or equal to Rs 10,000with a minimum incentive of Rs 2/- and maximum incentive of Rs 50/- per transaction. Maximum incentive is restricted to Rs 2,000/- per merchant per month. No incentive is to be offered to the bank.
- Entire incentive of 0.5% of the transaction value has to be passed on to the merchant by the acquiring bank and no part of the incentive can be retained by the acquiring bank to defray any of its banking/operating costs.

1.3 Paragraph 3.1 –

b. The minimum and maximum transactions values eligible under the incentive program is Rs 25 and Rs 10,000 respectively.

1.4 Paragraph 3.2 –

ii. BHIM Aadhaar incentive scheme is meant to defray the operational cost of the merchant and promote BHIM Aadhaar based digital payment transactions.

2. Annexure 1 –

a. "Valid Financial Transactions – Transaction amount greater than or equal to Rs 25 and less than or equal to Rs 10,000".

3. Other terms and conditions remain unchanged.

GOPALAKRISHNAN S., Jt. Secy.

RAKESH SUKUL

Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2018.05.15 18:35:11 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

भारत सरकार
Government of India
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
Ministry of Electronics & Information Technology
इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन / Electronics Niketan
6, सी जी ओ कॉम्पलेक्स / 6, C G O Complex
नई दिल्ली-110003 / New Delhi-110003
Website: www.meity.gov.in

Gopalakrishnan S., IAS
Joint Secretary
दूरभाष / Tele: Tel.: 24363075
Email: js.gopal@meity.gov.in
अ० स० पत्र स०
D.O.No. ....No. 12(23)/2017-DPD

दिनांक / Dated..........26.04.2018..........

Sub.: Publicizing of MDR Waiver and revised BHIM incentive schemes

Sir/Madam,

Ministry of Electronics & IT (MeitY) has been mandated to promote digital transactions in the country. MeitY has been co-coordinating with all the Ministries / Departments / States to achieve the target of 2500 Crore digital payment transaction, set for FY 2017-18, by Hon'ble Finance Minister.

2. The efforts made by all Ministries/Departments/States for promotion of digital payments are appreciated, which resulted in significant growth in digital payment transactions from 1003 Cr. in 2016-17 to 2060 Cr. in 2017-18. The details of mode-wise growth in digital payments have been enclosed as Annexure A.

3. MeitY is now working with renewed focus to further strengthen the digital payment ecosystem in the country. Recently, Government of India Vide Gazette Notification No. 6(19)/2017-DPD-1. dated 27.12.2017 (attached) has waived off Merchant Discount Rate (MDR) applicable on Debit Card/BHIM UPI/Aadhaar-Pay transactions less than or equal to Rs. 2000/- in value for a period of two years with effect from 1st January, 2018. This will help to promote small value transactions upto Rs. 2000/-.

4. Further, Government of India has recently revised and extended the following incentive schemes with effect from 1st April 2018 till 31st March 2019 for promotion and wider adoption of digital payment.

- BHIM cashback scheme for individuals
- BHIM incentive scheme for merchants
- BHIM Aadhaar merchant incentive scheme

Digital India
Power To Empower

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

ELECTRONICS INDIA
Billion Needs Million Chips

5. Co-operation of all Ministries/Departments/States is expected to further improve the adoption of Digital Payments. It is requested that information regarding MDR waiver and BHIM incentive schemes, as mentioned above may be disseminated and widely publicized in all organizations (Attached Offices/ Affiliated bodies/Autonomous Societies/Public Sector Enterprises/ Section 8 companies/ Section 25 companies/ Statutory Organizations/ Company registered under Company Act 1956 etc.) under your Ministry / Department / States. It is further requested to appropriately display the above information in websites of your Ministry / Department / States and all concerned organizations.

With regards,

Yours faithfully,

(Gopalakrishnan S.)

Encl.: As above

To:

- **All Secretaries, Government of India**
- **Chief Secretaries of all States/UTs**

Copy To:

- **IT Secretaries of all States/UTs**

Annexure A: Growth of Digital Transactions in Last Five Years

Modes/Year	FY 2013-14	FY 2014-15	FY 2015-16	FY 2016-17	FY 2017-18	Growth rate	Source
Units	Vol (In Cr)	Vol (In Cr)	Vol (In Cr)	Vol (In Cr)	Vol (In Cr)		
RTGS	8.11	9.28	9.83	10.79	12.48	16%	RBI
EFT/NEFT	66.10	92.75	125.29	162.21	194.63	20%	RBI
IMPS	1.54	7.84	22.08	50.68	101.29	100%	NPCI
Credit card usage at POS	50.91	61.51	78.57	108.71	139.23	28%	RBI
Debit card usage at POS	61.91	80.81	117.36	239.93	328.20	37%	RBI
m-Wallet	10.75	25.50	60.40	163.00	306.72	88%	RBI
PPI Cards	2.56	5.89	14.35	33.31	44.31	33%	RBI
NACH	8.65	32.46	139.27	196.80	237.20	21%	NPCI
AEPS	-	-	9.47	34.45	98.24	185%	NPCI
BHIM UPI/USSD	-	-	-	1.75	91.53	5130%	NPCI
NETC	-	-	-	2.03	12.65	523%	NPCI
BBPS	-	-	-	0.01	2.56	25500%	NPCI
Internet Banking	-	-	-	-	145.92	Intra bank transactions captured from Banks	Banks
Mobile Banking	-	-	-	-	65.33		Banks
Others	-	-	-	-	170.30		Banks
Closed Loop	-	-	-	-	109.76		Wallet Companies
Transactions	210.53	316.04	576.62	1,003.67	2,060.35	105%	

*Data of Debt card, Credit card and PPI Data has not been published by RBI for the March, 2018. Calculation is been done on pro rata basis.

Note:

1. *Above mentioned modes are included in Digital Payment
2. Cash / Cheque / Demand Draft (DD) are not considered as Digital mode of payment.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 05] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 2, 2018/पौष 12, 1939
No. 05] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 2, 2018/PAUSHA 12, 1939

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2017

विषय : 2000 रु. या इससे कम मूल्य के डेबिट कार्ड /भीम यूपीआई/एईपीएस लेनदेनों पी एमडीआर प्रभार में छूट प्रदान करना।

सं. 6(19)/2017-डीपीडी-1:—

1. डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत डिजिटल अवसंरचना, डिजिटल शासन और डिजिटल सेवाएं उपलब्ध करवा कर भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने की परिकल्पना की गई है। डिजिटल भुगतान इको सिस्टम का संवर्धन डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का अनिवार्य अंग है और इसमें भारत की अर्थव्यवस्था को परिवर्तित करने तथा उन सभी लोगों के लिए वित्तीय सेवाओं का समावेशन करने की क्षमता है जो बचे रह गए हैं।

2. 1 फरवरी, 2017 को वित्त मंत्री ने अपनी बजट भाषण में वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए 2,500 करोड़ के डिजिटल भुगतान लेनदेनों के लक्ष्य की उद्घोषणा की थी।

3. डिजिटल भुगतान पारिस्थितिक तंत्र में, व्यापारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं विशेष रूप से भारत जैसे देश में जहां लगभग 90% व्यापारी किराने की छोटी दुकानों, स्थानीय आउटलेट इत्यादि के रूप में असंगठित क्षेत्र से आते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे विक्रेता, ऑटो/टैक्सी ड्राइवर इत्यादि हैं, जो असंगठित व्यापारियों का बड़ा हिस्सा हैं। इनमें से प्रत्येक व्यापारी की लेनदेन राशि आमतौर पर छोटी होती है।

4. जब डेबिट कार्ड/भीम यूपीआई/आधार-पे भुगतान इकोसिस्टम में कोई भुगतान पीओएस मशीन या क्यूआर "स्कैन और भुगतान" या ऑनलाइन भुगतान मोड के माध्यम से व्यापारी बिक्री बिन्दु (पीओएस) पर किया जाता है तो व्यापारिक छूट दर (एमडीआर), व्यापारी द्वारा उसके बैंक (अधिग्रहणकर्ता) को देय होती है।

5. आरबीआई ने 6 दिसम्बर, 2017 को डेबिट कार्ड लेनदेनों के लिए लागू एमडीआर पुन: संशोधित करते हुए एक निदेश जारी किया है जो 01.01.2018 से प्रभावकारी होगा जिसमें लेनदेनों के लिए व्यापारी श्रेणीवार विशिष्ट एमडीआर दरें प्रस्तावित की गई हैं।

6. सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि छोटे लेनदेन जो 2000 रुपए या इससे कम मूल्य के हैं, पर एमडीआर शुल्क वापस किया जाएगा ताकि ऐसे डिजिटल भुगतान लेनदेनों को बढावा दिया जा सके। व्यापारी के लिए ऐसे लेनदेनों पर एमडीआर प्रभावकारी रूप से शून्य हो जाएगा और अत: वे नकद लेनदेन के बराबर हो जाएंगे। इस योजना की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नानुसार हैं :-

i. 1 जनवरी, 2018 से 2000 रुपए या इससे कम मूल्य वाले लेनदेनों पर डेबिट कार्ड/भीम यूपीआई/आधार-पे लेनदेनों पर लागू एमडीआर, दो वर्षों की अवधि के लिए सरकार द्वारा वहन किया जाएगा और ऐसे अधिग्रहणकर्ता बैंकों को इसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी ताकि ऐसे लनदेनों के संबंध में व्यापारियों को कोई एमडीआर न देना पड़े। तदनुसार, इस योजना के अतंर्गत बैंक सभी पात्र लेनदेनों के लिए व्यापारियों से कोई एमडीआर शुल्क वसूल नही करेंगे और इसके परिणामस्वरूप एमडीआर को कारण बताकर ग्राहकों से अधिक शुल्क नहीं लिया जाएगा।

ii. 2000 रुपये या इससे कम मूल्य वाले लेनदेनों के मामले में कोई एमडीआर लागू नहीं होगा। तथापि, 2000 रुपए से अधिक के लेनदेनों पर, एमडीआर पूरे लेनदेन मूल्य पर लागू होगा। उदाहरण के तौर पर, 1800 रुपए मूल्य के लेनदेन के मामले में कोई एमडीआर लागू नहीं होगा और 2300 रुपए के लेनदेन के संबंध में, एमडीआर पूरे 2300 रुपए के लेनदेन पर लागू होगा।

iii. प्रत्येक अधिग्रहणकर्ता बैंक को यह सुनिश्चित करना है कि आरबीआई के प्रासंगिक अनुदेशानुसार, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड दोनों को सम्मिलित करने वाले व्यापारियों के साथ कोई "बाध्य" करारनामा नहीं होना चाहिए।

iv. दिनांक 6.12.2017 के आरबीआई के निदेशानुसार करारनामों में यह खंड सम्मिलित होना चाहिए कि डेबिट कार्ड/भीम यूपीआई/आधार-पे के जरिए भुगतानों को स्वीकृत करते समय व्यापारियों द्वारा एमडीआर शुल्क का बोझ ग्राहकों पर नहीं डाला जाएगा।

v. प्रत्येक अधिग्रहणर्ता बैंक को निर्धारित किए जाने वाले प्रारूप में संबंधित प्रतिपूर्ति दावे को प्रस्तुत करना होगा।

vi. ऐसे दावे के साथ यह प्रमाणपत्र लगाना होगा कि जारीकर्ता बैंक और कार्ड नेटवर्क ऑपरेटर पर बकाया एमडीआर प्रभार के शेयर का पूर्णत: भुगतान कर दिया गया है और अधिग्रहणकर्ता बैंक के शेयर को स्पष्ट रूप से चिन्हित कर लिया गया है।

vii. प्रत्येक तिमाही के लिए अधिग्रहणकर्ता बैंक, डेबिट कार्ड/ भीम यूपीआई/आधार पे लेनदेनों (ऑन-यूएस और ऑफ़ यूएस लेनदेनों का अलग-अलग प्रदर्शन करने वाले) की मात्रा और मूल्य संबंधी अपने सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा यथा प्रमाणित एक रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

viii. दावे के साथ-साथ अधिग्रहणकर्ता बैंक अपने लेखापरीक्षक से प्राप्त एक प्रमाणपत्र आरबीआई के समक्ष प्रस्तुत करेगा जिसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जांचे जा रहे दावों के संबंध में एमडीआर का शुल्क न तो व्यापारी द्वारा उपभोक्ता से लिया गया है और न ही बैंक द्वारा व्यापारी से यथा लागू कम मूल्य के लेनदेन के लिए लिया गया है।

ix. यह योजना भारत में प्रचालन करने वाले बैंकों पर तथा भारत में किए गए लेनदेनों पर लागू है।

x. दिनांक 01.01.2018 से अधिग्राहक बैंकों को एमडीआर की पूतिपूर्ति संबंधी मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए स्थापित समिति ने भारतीय बैंक संघ (आईबीए) और अग्रणी अधिग्राहक बैंकों से प्राप्त इनपुटों का परीक्षण किया है और दिनांक 1.1.2018 से एक तिमाही के लिए कम मूल्य के ऐसे लेनदेनों पर एमडीआर की प्रतिपूर्ति के संबंध में 2000 रुपये अथवा इससे कम मूल्य के कुल डेबिट कार्ड लेनदेनों के मूल्य के 0.40% कैप का सुझाव दिया है। समिति ने यह सुझाव भी दिया है कि प्रतिपूर्ति के लिए एक विस्तृत सलाहकार प्रक्रिया भी की जा सकती है।

xi. अत: दिनांक 01.01.2018 से शुरू होने वाली 1 तिमाही के लिए अधिग्राहक बैंकों के लिए एमडीआर प्रतिपूर्ति पर कैप होगा जो 2000 रुपये या इससे कम के डेबिट कार्ड/भीम यूपीआई/आधार-पे लेनदेनों के कुल मूल्य के 0.40% पर होगा।

xii. सलाहकार प्रक्रिया जिसमें आरबीआई, आईबीए और बैंक शामिल हैं के माध्यम से ऐसे कम मूल्य वाले लेनदेनों के संबंध में प्रतिपूर्ति तंत्र तैयार किया जाएगा । इसके बाद तिमाही आधार पर एमडीआर की प्रतिपूर्ति हेतु अधिग्राहक बैंकों के लिए प्रक्रिया तैयार की जाएगी तथा इसके विषय में संबंधित सभी को जानकारी दी जाएगी।

7. बैंकों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि 01.01.2018 से कम मूल्य के लेनदेनों के लिए एमडीआर प्रतिपूर्ति की इस नई योजना में परिवर्तन निर्विघ्न रूप से किया जाए।

गोपालकृष्णन एस. संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2017

Subject : Subsidizing MDR charges on Debit Cards/BHIM UPI/AePS transactions of value less than or equal to Rs. 2000/-.

No. 6(19)/2017-DPD-1.—

1) The Digital India Programme envisions transforming India into a digitally empowered society and knowledge economy by making available digital infrastructure, digital governance and digital services to every citizen. Promotion of digital payments ecosystem is an essential aspect of the Digital India programme and has the potential to transform India's economy and extend inclusion of financial services to all those who remain excluded.

2) Finance Minister in his Budget Speech on February 1, 2017 had announced a target of 2,500 crore digital payment transactions for FY. 2017-18.

3) In the digital payments ecosystem, merchants play a very crucial role especially in a country like India where nearly 90% of merchants are from the unorganized sector in the form of small grocery stores, local outlets, etc. Besides, there are vendors, auto/taxi drivers etc., who constitute a large share of unorganized merchants. The transaction amount at each of these merchants is generally small.

4) In the Debit Card/BHIM UPI/Aadhaar-Pay payment eco system, when any payment is made at a merchant Point of Sale (POS) through a POS machine or QR "scan & pay" or online mode of payment, Merchant Discount rate (MDR) charge is payable by the merchant to his bank (Acquirer). A portion of this is shared by the acquirer bank with the card issuing bank and the card network operator.

5) RBI has issued a directive on 6th December, 2017 revising MDR applicable for debit card transactions which will be effective from 01.01.2018 wherein merchant category wise differential MDR rates have been proposed for transactions.

6) It has been decided by the Government to reimburse the MDR charges on small transactions which are less than or equal to Rs. 2000/- in value so that such digital payment transactions are promoted. The MDR on such transactions for the merchant will effectively become zero and hence they will come on par with cash transactions. The salient features of the scheme are as follows:-

   i) MDR applicable on Debit Card/BHIM UPI/Aadhaar-Pay transactions less than or equal to Rs. 2000/- in value will be borne by Government for a period of two years with effect from 1st January, 2018 by reimbursement of the same to the acquirer banks so that no MDR is payable by the merchant in respect of such transactions. Accordingly, the banks shall not charge any MDR from merchants for all eligible transactions under this scheme and consequently the consumers will not be overcharged citing MDR as a reason.

   ii) No MDR will be applicable in case of transaction value less than or equal to Rs. 2000/-. However, for transaction value above Rs. 2000/-, MDR would be applicable on the entire transaction value. For example, no MDR will be applicable in case of a transaction value of Rs.1800 and in respect of a transaction of Rs. 2300/-, MDR would be applicable on the entire transaction value of Rs. 2300/-.

1291/8/16

iii) Each acquirer bank has to ensure that in accordance with the relevant RBI instructions, there should be no "bundled" agreement with the merchants covering both debit cards & credit cards.

iv) In line with the RBI instructions dated 6.12.2017, the agreements should include a clause that MDR charges should not be passed on by the merchants to the customers while accepting payments through debit cards/BHIM UPI/Aadhaar Pay.

v) Each acquirer bank will be required to submit their respective reimbursement claims in the format to be laid down.

vi) Such claim shall be accompanied with a certificate that the share of the MDR charges that is due to the issuer bank and the card network operator have been paid in full and the share of the acquirer bank has been clearly identified.

vii) For every quarter the acquirer banks should submit a report duly certified by their statutory auditors regarding the volume and value of the debit card/BHIM UPI/Aadhaar Pay transactions (showing on-us and off-us transactions distinctly).

viii) Along-with the claim, the acquirer banks should submit to the RBI, a certificate from their auditor confirming that with respect to the claim under examination, MDR has neither been charged from the consumer by the merchant nor charged by the bank from the merchant in respect of the applicable low value transactions.

ix) The Scheme is applicable to banks having operations in India and transactions done in India.

x) The Committee set up to look into the issues relating to reimbursement of MDR to the acquirer banks with effect from 1.1.2018, has examined the inputs from Indian Banks Association (IBA) and leading acquirer banks and has suggested a cap of 0.40% of value of total debit card transactions less than or equal to Rs. 2000/- with regard to reimbursement of MDR on such low value transactions for a period of one quarter with effect from 1.1.2018. The committee has also recommended that a detailed consultative process for the reimbursement may be worked out.

xi) Therefore, for a period of one quarter starting from 1.1.2018 there will be a cap on MDR reimbursable to the acquirer banks which will be at 0.40% of the total value of the debit card/ BHIM UPI / Aadhaar Pay transactions less than or equal to Rs. 2000. If felt necessary this cap could be revisited thereafter.

xii) The reimbursement mechanism in respect of such low value transactions would be evolved through a consultative process involving the RBI, IBA and banks. Thereafter, the procedure for quarterly reimbursements of MDR to the Acquirer banks will be worked out and communicated to all concerned.

7) The banks are requested to ensure that the transition to this new scheme of MDR reimbursement for low value transactions w.e.f 1.1.2018 is done smoothly without any hitch.

GOPALAKRISHNAN S., Jt. Secy.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2018.01.02 19:37:35 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.